



2026:AHC: 2938

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19635 वर्ष 2025

सब इंस्पेक्टर उम्मेद सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

|                             |   |                                               |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------|
| याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता | : | अतुल कुमार, पी. अमित कुमार, सत्यम कुमार वर्मा |
| प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता   | : | सी.एस.सी.                                     |

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह कमिश्नरेट गाजियाबाद से अपने गृह जनपद- अलीगढ़ या किसी अन्य निकटवर्ती जिले में स्थानांतरण चाहता है और वह एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है। वह दिनांक 06.05.2025 के शासनादेश पर भरोसा करना चाहता है।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. ऐसे सुझाव पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जो इसे प्राप्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे को तय करने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 2 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उसे प्रेषित कर दिए जाएं।

7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)